RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-04
Issue-04
April-2019

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com [UGC Listed Journal]

आधुनिक भारत में महिला और सामाजिक सुधार आंदोलनों में नारियों का योगदान

[1]Manju Bala and [2]Dr. Jayveer Singh

[1]Research Scholar, OPJS University, Churu, Rajasthan
[2]Associate Professor, OPJS University, Churu, Rajasthan

ARTICLE DETAILS

Article History
Published Online: 15 April 2019

Keywords
आधुनिक भारत, महिला, सामाजिक आंदोलन, महिला आंदोलन, महिला उत्थान

ABSTRACT

भारत में महिला आंदोलनों ने दो चरणों में काम किया पहला महिला उत्थान और दूसरा पुरुषों और महिलाओं के लिए समान अधिकारों की लड़ाई। विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक दस्तावेजों का अध्ययन करने से जो भारतीय महिलाओं के आंदोलन को छूते हैं, एक तुलनात्मक संभावना भारत में नारीवादी आंदोलनों पर प्रस्तावों के निर्माण के लिए मामूली योगदान देने के लिए आएगी। इस पत्र के माध्यम से मेरा मुख्य उद्देश्य सभी आयामों से महिला आंदोलनों पर शोध करना और उन्नीसवीं और बीसवीं भारत के विभिन्न वैचारिक सामाजिक सुधार के आंदोलनों से गुजरना और महिलाओं को एक विषय और मुद्दे के रूप में अध्ययन करना होगा। मेरे पत्र में यह भी शामिल होगा कि ब्रिटिश काल के दौरान महिलाओं के मुद्दे सामाजिक सुधार आंदोलनों में कैसे अविभाज्य रहे।

प्रस्तावना

उन्नीसवीं शताब्दी में, महिला प्रश्न सभी सामाजिक–धार्मिक सुधार आंदोलनों का केंद्र था। लेकिन उनका मूल प्रश्न यह नहीं था कि महिलाएं क्या चाहती हैं बल्कि उन्हें कैसे आधुनिक बनाया जा सकता है। अपने सभ्यता मिशन के तहत उन्होंने महिलाओं के प्रति अपने व्यवहार के लिए भारतीय धर्म, संस्कृति और समाज की निंदा की। यूरोप में प्रबुद्धता के सुधारवादी और पुनर्जागरण के आदर्शों को आमतौर पर इतिहासकारों द्वारा उद्धृत किया गया है क्योंकि उन्नीसवीं शताब्दी के भारत में शुरू किए गए सामाजिक सुधारों की प्रेरणा। 19 वीं शताब्दी में भारत में महिलाओं के प्रति समाज के व्यवहार की समस्याओं ने पश्चिमी मानवीय विचारकों, ईसाई मिशनरियों और भारतीय सामाजिक–धार्मिक सुधारकों का ध्यान आकर्षित किया। सामाजिक–धार्मिक सुधार आंदोलनों के तहत सुधारकों ने सती, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, बहुविवाह, दहेज और देवदासी प्रथा के निषेध जैसे भारतीय समाजों की महिलाओं के प्रति बुरे व्यवहारों के खिलाफ आवाज उठाई। उनके विचारों को मजबूत किया गया जब ब्रिटिश सरकार ने अपने स्वयं के पुराने धार्मिक शिलालेखों से डेटा एकत्र किया और ऐसे सामाजिक रीति–रिवाजों की बुराइयों को उजागर किया। इसके अलावा, भारत और इंग्लैंड के कुछ प्रबुद्ध ब्रिटिश अधिकारियों ने भी उन सामाजिक बुराइयों को दूर करने के उपाय शुरू किए। उन्होंने हिंदू समाज के प्रतिक्रियावादी वर्ग के कड़े विरोध के खिलाफ इसके उन्मूलन के समर्थन में जनमत जुटाया। शिक्षित महिलाएं जो अब अपने प्राकृतिक अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही थीं, बाकी महिलाओं को भी आजाद करने के लिए आगे आईं। इसलिए, भारत में उन्नीसवीं शताब्दी ने महिलाओं को पीड़ा देने के लिए कई आवाजें दीं और अपने प्राकृतिक अधिकारों और स्थानों के लिए खड़े हुए जो उन अधिकारों का पहला आधार पत्थर बन गए जिन्होंने भविष्य में हमारे समाज की कई बुराइयों को जड़ से उखाड़ फेंका।

सती प्रथा

अठारहवीं शताब्दी के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ सुधार से प्रभावित होने वाले ब्रिटिश उपनिवेशवादी के रूप में भारत आए। अपने आर्थिक और राजनीतिक लाभ प्राप्त करते हुए उन्होंने वर्तमान भारतीय समाज में कुछ बदलाव या सुधार लाने की कोशिश की। अंग्रेजों ने पहली बार 1765 में बंगाल में अपनी सरकार स्थापित की। बहुत जल्द उनके लिए यह स्पष्ट हो गया कि भारतीय समाजों की परंपराओं और मानदंडों को सीखे बिना वे प्रशासन में कभी सफल नहीं हो सकते। इस तरह उन्होंने भारतीय इतिहास और उसके स्रोतों को पढ़ना शुरू किया। राजनीतिक सर्वोच्च होने के नाते उन्होंने कठोर और निश्चित सामाजिक मानदंडों से संबंधित कई कानून पारित किए। यूरोपीय लोगों द्वारा प्रारंभिक लेखन का उद्देश्य हिंदू परंपराओं की खासियत को उजागर करना था। उन्होंने महिला मुद्दों से जुड़े मुद्दों को उठाने की कोशिश की। बंगाली समाज का पहला नकारात्मक पहलू जो उनके सामने आया, वह था सती प्रथा। भारत में इवेंजेलिकल, यूटिलिटेरियन और एंग्लिसिस्टों का ध्यान केंद्रित हमला उन प्रथाओं पर था, जिन्हें भारतीय लोगों की यौन दुर्बलताओं का सूचक घोषित किया गया था। लंबे समय तक ब्रिटिशों ने अपनी गैर–आर्थिक नीतियों के तहत सती होने पर कानून बनाने से इनकार कर दिया। लेकिन जल्द ही राजा राम मोहन राय जैसे कई भारतीय समाज सुधारकों ने भी इस क्रूर प्रथा के खिलाफ सामाजिक आंदोलन शुरू कर दिया। इस मुद्दे के लिए सरकार की जांच से संबंधित पहला रिकॉर्ड 1789 में किया गया था। इसे 1798 तक बंगाल में गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था। लेकिन भारत के अन्य हिस्सों में भी यह प्रथा जारी रही। 1815 से 1824 के बीच लगभग 6632 मामले ब्रिटिश साम्राज्य की केवल तीन प्रेसीडेंसी में दर्ज किए गए थे। जिसमें से 80: मामले केवल बंगाल के थे। अब इस क्रूर व्यवस्था के उन्मूलन के लिए कानून का बचाव करने के लिए भारतीय शिलालेखों से साक्ष्य एकत्र करना शुरू किया गया। रॉय का फारसी काम तुहफत अल मुवहद्दीन (ए गिफ्ट टू डीस्ट्स) अपने समय के लिए किया गया सबसे अच्छा काम था। उसने उन तरीकों को वजह दी जो धर्म को पूरी तरह से नकारने के करीब आए। उन्होंने खंडित विधवा अलगाव की धारणा को तपस्वी विधवा के साथ बदलने की कोशिश की। इस प्रकार, 4 दिसंबर 1829 को

RRIJM 2015, All Rights Reserved

बंगाल और फिर 2 फरवरी 1830 को मद्रास में ष्रेगुलेशन ग्टप्प्ष द्वारा आधिकारिक रूप से सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया था। 4 दिसंबर 1829 के विनियमन ग्टप्प् का कहना है कि श्सुत का अभ्यास, या जलने या दफन को जीवित घोषित करना। हिंदुओं की विधवाएं, आपराधिक अदालतों द्वारा अवैध और दंडनीय। श

सामाजिक सुधारों के लिए अभियान की इस कार्रवाई ने राजनीतिक और वैचारिक संदर्भ में सरकार को सर्वोच्चता प्रदान की। हालांकि यह अधिनियम इस प्रथा को पूरी तरह से रोकने में सक्षम नहीं था। औपनिवेशिक प्राधिकरण से स्वतंत्रता मिलने के बाद भी, इस प्रणाली के अभ्यास की घटनाएं देखी जाती हैं। लेकिन जब इस कानून को लागू किया गया तो हिंदू समाज ने मिश्रित प्रतिक्रिया दी, जैसे द हिंदू लिटरेरी सोसाइटी, ट्रिप्लिकेन लिटरेरी सोसाइटी, प्रोग्रेसिव सिटिजन सोसाइटी ऑफ मद्रास आदि ने इसे नए युग की शुरुआत के रूप में स्वीकार किया। द हिंदू लिटरेरी सोसाइटी की पत्रिका मे क्रिसेंट 'ने इस अधिनियम को पारित करने के लिए सरकार की प्रशंसा की, क्योंकि यह भारतीय महिला लोगों के लिए एक आशीर्वाद था और उम्मीद थी कि यह सैकड़ों युवा महिलाओं को दर्दनाक सामाजिक बुराइयों से छुटकारा दिलाएगा। ट्रिप्लिकेन लिटरेरी सोसाइटी ने इसे ष्भारत की महिला लोक के लिए एक रक्षक के रूप में स्वागत किया क्योंकि यह प्राचीन काल से महिलाओं पर चल रहे सामाजिक कलंक को दूर करेगाष्। दूसरी ओर, कुछ रूढ़िवादी हिंदुओं ने 19 जनवरी, 1830 को भारत के गवर्नर–जनरल को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें दावा किया गया कि श्सतीश प्रथा एक आंदोलनकारी थी और मनु धर्मशास्त्र द्वारा अनुमोदित थी और इसलिए अधिनियम कुछ भी नहीं था, लेकिन उल्लंघन पर हिंदू कानून और इसलिए सरकार को इसे तुरंत वापस लेना चाहिए। उनके द्वारा 7 फरवरी 1832 को मद्रास प्रेसीडेंसी के गवर्नर को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि यह अधिनियम सरकार की–गैर–हस्तक्षेप नीति 'के खिलाफ था और यह अधिनियम हिंदू राष्ट्र के आर्थिक नियमों को ध्वस्त करेगा। उन्होंने आगे बताया कि इस अधिनियम के माध्यम से सरकार हिन्दू धर्म को समाप्त करने के माध्यम से भारतीयों को धर्मांतरित करती दिख रही थी। जो भी प्रतिक्रियाएं थीं लेकिन यह सच था कि यह कानून आगे चलकर एक पहचान योग्य सुधारवादी विचारधारा थी। विचारधारा, जो विशेष रूप से महिलाओं के दृष्टिकोण में, आने वाली शताब्दी के अधिकांश समय में बरकरार रखी गई थी।

बाल विवाह

अपने 35 वर्षीय पति हरि मोहन मैती के हाथों दस साल की बच्ची फूलमनी दास की मौत और रुखमाबाई के मामले में, जिन्होंने अपने अशिक्षित, संवेदनशील और बेरोजगार पति दादाजी भिकाजी के साथ रहने से इनकार कर दिया, सरकार ने सामाजिक सुधारकों के दबाव में महसूस किया शादी की उम्र तय करने की आवश्यकता। यह संघर्ष उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में शुरू हुआ। केशब चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महादेव गोविंद रानाडे आदि जैसे महान नेताओं ने आवाज उठाई। सुधारकों ने यह भी महसूस किया कि बाल विवाह की प्रथा भारत की महिलाओं से संबंधित अन्य सामाजिक बुराइयों का मुख्य कारण है। ब्रह्मो समाज और आर्य समाज जैसे सामाजिक सुधार आंदोलनों ने पति के हाथों बच्चे की पत्नी को शारीरिक कष्ट और उत्पीड़न से बचाने के लिए एक विशेष कानून की आवश्यकता की मांग की। कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे के कस्बों में, यह बलात्कार और हत्या का मामला बन सकता है, इसलिए जिम्मेदार व्यक्ति को सजा के रूप में मौत दी जा सकती है यदि लड़की आठ वर्ष से कम उम्र की है और उसे 1828 से आपराधिक कोड के तहत दंडनीय घोषित किया गया था। 1846 में जब विधि आयुक्तों ने भारतीय दंड संहिता का मसौदा तैयार किया, तो उन पत्नियों को बलात्कार का दंड देने का फैसला किया, जिन्होंने कम उम्र की पत्नियों के साथ विवाह का उपभोग किया था। सबसे पहले, भारतीयों की ओर से यह मुद्दा ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा उठाया गया जिन्होंने अपने लेखन के माध्यम से इस मुद्दे को उठाया। परिणामस्वरूप, 1850 में सरकार ने 10 वर्ष का निर्णय लिया, जिसमें बालिकाओं के साथ यौन संबंध बनाने की सहमति की उम्र थी, चाहे विवाहित या अविवाहित और अपराधी को बलात्कारी माना जाता था और 1860 के भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दंडनीय था। तब ईश्वर चंद्र सेन, नई शादी की व्यवस्था के तहत उनकी संस्था में, जिसने न केवल दूल्हे से बल्कि दुल्हन से भी सहमति लेना अनिवार्य कर दिया। उन्होंने सरकार से भारत में बाल विवाह के खिलाफ गंभीर कार्रवाई करने का अनुरोध किया क्योंकि उन्होंने इसे कई अन्य सामाजिक बुराइयों का मूल कारण माना। उन्होंने 1870 और 80 के दशक में अपने प्रयासों को जारी रखा। उनके रेखांकित प्रयासों के तहत 1872 के मूल विवाह अधिनियम प्प् में ब्रह्म समाज के विवाह के रीति–रिवाजों को फिर से शामिल किया गया। जिसमें बहुविवाह के खिलाफ निषेधाज्ञा लागू की गई, महिलाओं को तलाक, जातिविहीन विवाह और 14 और लड़कियों और 18 के विवाह के लिए न्यूनतम आयु की स्थापना का कानूनी अधिकार दिया गया। पुरुषों के लिए। पहले इन सुधारों का केंद्र बंगाल था, लेकिन जल्द ही यह भारत के अन्य हिस्सों और विशेष रूप से महाराष्ट्र में स्थानांतरित हो गया। यहाँ इस मुद्दे को बेहरामजी मालाबारी ने जोरदार ढंग से उठाया, जो पेशे से पत्रकार थे। उनका प्रभावशाली कार्य शिशु विवाह और लागू विधवापन पर नोट्स था, जो कि जनगणना द्वारा उत्पन्न सांख्यिकी पर आधारित था, और सहमति की आयु को विनियमित करने के लिए एक तर्क था। उन्होंने भारत में बालिकाओं की सुरक्षा की तुलना की और एक तुलनीय विनियमन के तहत अंग्रेजी लड़कियों को सुरक्षा प्रदान की। सुधारवादी बदलाव लाने के लिए उन्होंने निम्नलिखित की वकालत कीरू

1. राष्ट्रीय संघ का गठन।
2. बाल विवाह के विषयों पर पाठ और विधवाओं की समस्याओं को शैक्षिक पुस्तकों में प्रस्तुत करना
3. विश्वविद्यालय द्वारा एक संकल्प को लागू करना कि कुछ वर्षों के बाद जो स्नातक नहीं थे उन्हें विश्वविद्यालय की डिग्री के लिए योग्य माना जाएगा।

हिंदू श्रमिक पुनर्विवाह संघ ने यह आग्रह किया कि प्रत्येक स्नातक को बाल विवाह को हतोत्साहित करना चाहिए। उनके काम को महादेव गोविंद रानाडे द्वारा कुछ हद तक लिया गया था, जो प्रमुख आस्तिक और समाज सुधारक थे। उन्होंने श्स्मृतिश और श्श्रुतिश पर संदेह किया और उन्हें तीन तरीकों से विवाह की आयु कम करने का दोषी ठहराया ए।

लड़कियों को अविवाहित जीवन का निषेध करके, ख। माता–पिता के लिए अपनी बेटियों की यौवन से पहले शादी करना अनिवार्य बनाकर, सी। कन्यासी (स्त्रीलिंग) आदि शब्दों के नए अर्थ का आविष्कार करके।

इसलिए, उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि विवाह योग्य आयु को धीरे–धीरे उपरोक्त कारणों से नीचे लाया गया था। बॉम्बे के बेहरामजी मालाबारी, जो कि व्यापक रूप से बाल विवाह के रिवाज के खिलाफ संघर्ष के लिए जाने जाते हैं, ने माना कि प्रारंभिक विवाह के कारण कई परिणाम होते हैं, जैसे कि लड़कों को काफी कम उम्र में अपनी पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, लड़कियों ने बीमार बच्चों को जन्म दिया और उन्हें कई महीनों तक भोजन करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यह महिला शिक्षा और महिलाओं की प्रगति में भी बाधा थी। उन्होंने लड़कियों और लड़कों के लिए क्रमशः सोलह और पच्चीस वर्ष की आयु निर्धारित की। वह इन सामाजिक समस्याओं में सरकारी हस्तक्षेप के पक्ष में थे।

लेकिन यह राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत थी जिसके परिणामस्वरूप सभी ब्रिटिश सुधारों से इनकार कर दिया गया था। बाल गंगा धर तिलक भारतीय परंपरा के सुधार के सबसे मुखर विरोधियों में से एक थे। वह भारतीय परंपरा में सुधारों के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने यहां तक कहा कि रुखमाबाई के पति के साथ रहने से इनकार करने का मामला महिला शिक्षा का परिणाम है। इस पुनरुत्थानवादी भूग्रस्त के पश्चिमी–विरोधी तत्व का मुस्लिम विरोधी भावनाओं के साथ–साथ अन्य खतरनाक प्रभाव भी था। एक्ट ग्ट के तहत 1877 में इस तरह के विपक्षी दबाव के तहत, रुखमाबाई के मामले में फैसला उसके पति के पक्ष में गया। उसके बाद तलाक की अवधारणा को पेश करने का प्रयास किया गया, जिसे अंततः 1923 के अधिनियम ग्ग्प के तहत अनुमति दी गई थी।

इसी दौरान मुसलमानों में भी आंदोलन शुरू हुए। यहाँ तक कि एम। ए। जिन्ना ने यह कहते हुए बाल विवाह का विरोध किया कि दुनिया में कहीं और भी इस तरह के कुकृत्य प्रचलित हैं। यह उन पर हिंदू समाज के प्रभाव का एकमात्र परिणाम था। यहां तक कि पैगंबर मोहम्मद ने महिलाओं के खिलाफ भेदभाव का विरोध किया है और वह खुद इस संबंध में सर्वश्रेष्ठ पुरुष का सबसे अच्छा उदाहरण थे। मार्च 1891 में, भारतीय दंड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता दोनों में संशोधन किया गया और लड़की की शादी की उम्र को बढ़ाकर 12. कर दिया गया। व्यावहारिक रूप से इस कानून से हिंदू समाज में शायद ही कोई फर्क पड़ा लेकिन इससे यह मामला सुर्खियों में आ गया। अब सामाजिक और राजनीतिक दोनों जन आंदोलनों ने अपने जनमत संग्रह में इस बिंदु को शामिल किया। यहां तक कि मैसूर जैसी रियासतों ने भी अपने क्षेत्रों में इस कानून को लागू करने की कोशिश की। भारत में बीसवीं सदी की शुरुआत राजनीतिक बलों के नक्षत्र में मजबूत बदलाव और कांग्रेस के भीतर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में महिलाओं के उभरने से हुई है। 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना की गई। विधानसभा में इसकी मजबूत मांग के तहत आखिरकार 1929 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित किया गया। जिसे नारी मुक्ति के इतिहास में शारदा अधिनियम के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह विधेयक विधानमंडल में हर बिल्ला सारदा द्वारा पेश किया गया था। 1927 में विधानसभा।

विधवा पुनर्विवाह और संपत्ति कानून

पारंपरिक हिंदू समाज में, एक विधवा को अपने पति की मृत्यु के बाद एक आभासी प्रकोप के रूप में रहना पड़ता था, जिसका अर्थ है कि उसे अपना सिर मुंडाने, अपने गहने त्यागने, एकांत में रहने और तपस्या के नियमित कार्यों से गुजरना पड़ता था। उस पर, बाल विवाह और आर्थिक रूप से निर्भरता ने स्थिति को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया। कई अमानवीय और अप्राकृतिक रीति–रिवाज नैतिकता के हित के लिए अत्यधिक पूर्वाग्रही रहे। सबसे पहले, विधवा अपरिपक्वता की प्रथा में महत्वाकांक्षा पर बहस ने इंडियन सोसाइटी में उच्च जाति की विधवाओं के अपमानजनक स्थिति को सामने ला दिया। उनकी हालत इतनी दयनीय थी कि वे नर्क के जीवन जीने के बजाय सती प्रथा के माध्यम से मृत्यु को प्राथमिकता देते थे। थॉमस मैकॉले के तहत 1830 के कानून आयोग में, उच्च दर के शिशु और पुनर्विवाह निषेध के बीच एक गहरा संबंध पाया गया। 1837 में उत्तर–पश्चिम प्रांत के सदर निजामत अदालत ने विधि आयोग को सूचित किया कि बाल हत्या एक प्रचलित अपराध था और सिफारिश की थी कि एक महिला के शरीर के गुपचुप तरीके से निपटान करके अपने मृत बच्चे के जन्म को छुपाने के प्रयास को अवैध बनाया जाना चाहिए। लेकिन विधि आयोग को इस सिलसिले में आगे की जाँच नहीं करनी चाहिए, इसलिए उन्होंने केवल वही पढ़ा जो उनके सामने था। चाहे वह कन्या शिशुहत्या हो या स्वास्थ्य संबंधी ऐसे कारणों की जांच नहीं की गई। इसलिए, 1837 के कलकत्ता, अल्लाहबाद, मद्रास और बॉम्बे के अपने पत्र के माध्यम से विधि आयोग ने पुनर्विवाह का कानून पारित होने पर जनता की प्रतिक्रिया के बारे में राय मांगी। सभी सदरे अदालतों ने सार्वजनिक प्रतिक्रिया की कड़ी चेतावनी के साथ नकारात्मक प्रतिक्रिया दी। विधवाओं की प्रथागत स्थिति पर विधायी चुनौती के सवाल को फिर से उठाए जाने से पहले लगभग 18 वर्ष का समय लग गया। यह समय भारतीयों का था। ईश्वरचंद्र विद्यासागर, संस्कृत के विद्वान, भावुक समाज सुधारक और पश्चिमी शिक्षित प्रगतिशील बंगाली लेखकों ने, एक प्रगतिशील पत्रिका, तातवाबोधिनी पत्रिका में अपने लेखन के माध्यम से इस मुद्दे पर अपनी आवाज उठाने की कोशिश की। उनकी सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति उनकी किताब भ्पदकन मैरिज ऑफ हिंदू विडो 'शीर्षक के माध्यम से थी, उन्होंने पाराशर धर्म संहिता से श्लोक उद्धृत किया, जो कलयुग में हिंदू कानूनों का एक सेट है, जिसे सागा प्रहार द्वारा लिखा गया है।

'गते मृते प्रवाजिते पलेवच पतित पितु ।।
पंचस्वापत्सु नारीनाम् पितरन्यो बिधियते '३

जिसका अर्थ है "महिलाएं फिर से शादी करने के लिए स्वतंत्र हैं, अगर उनके पति की बात नहीं सुनी जाती है, मर जाते हैं, दुनिया से रिटायर हो जाते हैं, नपुंसक साबित होते हैं या एक बहिष्कार करते हैं।"

उन्होंने 4000 हस्ताक्षरों के साथ एक याचिका तैयार की और इसे इस उम्मीद के साथ सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया कि सरकार इसे समय की मांग मानकर विधवा पुनर्विवाह कानून पारित करेगी। उनके काम ने बर्धमान के राजा महताबचंद बहादुर का ध्यान खींचा। उनके पास मजबूत समर्थक और साथ ही विरोधी थे। कुछ लोगों ने उन्हें हिंदू कानूनों के विद्वान कहा, जो यह कहकर निंदा करते हैं कि यह नैतिकता को कम करेगा और पति या पिता के सुरक्षात्मक

प्रभाव के बाहर खतरनाक गैर–पत्नी की कामुकता के बारे में चिंतित था। इस प्रकार 784 याचिकाएं यू.पी. और इस प्रयास के खिलाफ कलकत्ता पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवधि के दौरान नादिया, त्रबनी, भटपारा और बांसबारुह के हिंदू कानून के 991 प्रोफेसरों ने वेदों से शिलालेख, मनु की संहिता, महाभारत की पहली पुस्तक, आदित्य पुराण, रत्नाकर, निरान्या शुधोस, हेमाद्री और मदन पारिजात का उल्लेख किया, ताकि उस पक्ष का समर्थन किया जा सके। विवाह, बड़े भाई का बड़ा हिस्सा और एक तपस्वी के टोकन के रूप में मिट्टी के बर्तन को ले जाना, ये पांच कलियुग द्वारा निषिद्ध हैं। बंगाली समाज द्वारा मजबूत प्रतिरोध दिखाया गया था। इस कानून के खिलाफ 51,746 हस्ताक्षरित याचिकाएं भेज रहे थे। तब भी 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ग्ट कानून आयोग के एक सदस्य के तर्क के साथ पारित किया गया था ष्यदि एक ही हिंदू पिता के सीखने, कारण, और विवेक ने उसे अपने छोटे बच्चे को दुख के जीवन से बचाने या कानून के विरुद्ध निर्देशित किया। देश के रास्ते में नहीं खड़ा होना चाहिए ”।

षहिंदू पुनर्विवाह सोसाइटीष का गठन 1873 में नागरकोइल में किया गया था। जी। सुब्रमण्य अय्यर, राव बहादुर पी। आनंदाचारलु और अन्य जैसे नेताओं ने विधवा पुनर्विवाह की आवश्यकता की वकालत की। उन्होंने न केवल विधवा पुनर्विवाह की वकालत की बल्कि अपनी ही बेटी जो विधवा हो गई थी, उसके लिए शादी की व्यवस्था करके एक मिसाल कायम की। एक संपत्ति के मालिकाना हक के अभाव का विधवा पुनर्विवाह पर एक प्रभाव था क्योंकि कोई भी अपनी लड़कियों की दूसरी शादी पर खर्च करने के लिए आगे नहीं आया। इसलिए युवा विधवाओं को संपत्ति प्राप्त करने के अधिकार और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को प्रभावी ढंग से निष्पादित करने के उद्देश्य से, कुलीन नागरिकों ने 1882 में मद्रास में हिंदू महिला पुनर्विवाह संघ नामक एक नई संस्था का आयोजन किया। इस एसोसिएशन ने 7 जून 1883 को अपना पहला विधवा पुनर्विवाह मनाया। वडालुर रामलिंगम पिल्लई ने महिलाओं को अपने पति की मृत्यु के बाद सफेद साड़ी नहीं पहनने के लिए कहा और उनसे अपनी आजीविका के लिए अपना पेशा अपनाने का आग्रह किया। तमिल भाषा में लिखे गए उपन्यासों ने महिलाओं की स्थिति पर सुधारकों की चिंता को दर्शाया। वेदनायगम पिल्लई के उपन्यास ष्प्रतिमा मुदलियार चरित्रमष और ष्सुगुना सुंदरीष, ष्पद्मावती चरिथिरमष, ष्कनकदंबल चरिथिरमष, आदि ने महिलाओं की अपमानजनक स्थिति की निंदा की और समाज को महिलाओं को समान दर्जा देने की अपील की। इन सभी प्रयासों के बावजूद, यह प्रयास किया गया। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि विधवा पुनर्विवाह लोगों के बीच लोकप्रिय नहीं था। सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी खुद महिलाएं थीं जिन्हें रूढ़िवादी कहा जा सकता है, इन शब्दों में, ष्हम एक बार पैदा होते हैं, हम एक बार मरते हैं और हम एक बार शादी करते हैंष। यह भी स्वीकार किया जाना चाहिए – हिंदू जनता। राय विधवा पुनर्विवाह पर दया नहीं करती थी और इसके साथ सहानुभूति रखने वाले कई लोग सकारात्मक कार्रवाई में अपनी सहानुभूति व्यक्त करने की हिम्मत नहीं करते थे। आर्थिक कल्याण के उपाय यह महसूस किया जाता है कि महिलाओं की दयनीय आर्थिक स्थिति संपत्ति के अधिकार से वंचित करने के कारण थी। महिलाओं के लिए संपत्ति के अधिकार को प्राप्त करने के बारे में प्रगति करने वालों ने महिलाओं की पीड़ा को कम किया। विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम 1874 में लागू किया गया था। अधिनियम के तहत, अलग संपत्ति महिलाओं को इस प्रकार शामिल किया गया थारू

1. कानून द्वारा अर्जित किसी भी रोजगार, व्यवसाय या व्यापार में विवाहित महिलाओं की मजदूरी और कमाई।
2. साक्षरता, कलात्मक और वैज्ञानिक कौशल के माध्यम से अर्जित धन।
3. इस तरह के वेतन और निवेश से सभी बचत और
4. उसकी अपनी ओर से प्रभावित बीमा की नीति को उसकी अलग संपत्ति माना जाना चाहिए, जिस पर उसका पूर्ण अधिकार होना चाहिए।

1937 के हिंदू महिलाओं के संपत्ति अधिनियम ग्टप्प् के तहत, और दयाभागा और मिताक्षरा कानून दोनों के तहत 1956 के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ग्ग्, विधवा ष्केवल एक बेटे, बेटे के बेटे, बेटे के बेटे के बेटे की अनुपस्थिति में अपने पति की संपत्ति में सफल रही। मृतक और वह संपत्ति जो उसने अपने पति के उत्तराधिकार में ली थी, वह एक संपत्ति थी जिसे उसने अपने जीवनकाल के लिए धारण किया था। ” उसकी मृत्यु के बाद, यह उसके पति के निकटतम रिश्तेदार के पास जाता है। लेकिन व्यावहारिक रूप से आज भी यह कानून केवल कागजों में है। खुद महिलाओं द्वारा भी इसका विरोध किया जाता है। पंजाब क्षेत्र में, विधवा पुनर्विवाह की रीति को करवा के नाम से जाना जाता है। इस प्रथा में विधवा का विवाह उसके पति के निकटतम पुरुष से किया जाता है। इससे उसके पति का हिस्सा बचेगा और यह परिवार में रहेगा। इस प्रकार, विधवा को पति के घर में रखकर महिलाओं की निरंतर शुद्धता की पुष्टि करने का एक तरीका है, जो संपत्ति में हिस्सेदारी को खोने के बिना है।

देवदासी प्रथा के खिलाफ कानून

देवदासी प्रथा के खिलाफ जो आंदोलन शुरू किया गया था, जिसमें लड़कियों को भगवान के प्रसाद के रूप में मंदिरों में भेजा जाता था और अठारहवीं शताब्दी तक यह कम या ज्यादा वेश्यावृत्ति के पेशे के रूप में बदल गया था, इतिहास में इसे नाहर विरोधी आंदोलन के रूप में जाना जाता है। पहला एंटी नच आंदोलन अठारहवीं शताब्दी में रिफॉर्म प्रचारकों द्वारा मुख्य रूप से राजा राम मोहन राय, पेरियार ई. वी.रामस्वामी, मुथ लक्ष्मी अय्यर, एस। मुथु मुदलियार, सर सीपी रामास्वामी अय्यर, एम। कृष्णन नायर जैसे विभिन्न सामाजिक सुधार आंदोलनों के प्रसिद्ध नेताओं द्वारा शुरू किया गया था। , सीएन अन्नादुरई, करुणानिधि, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, महादेव गोविंद रानाडे, धोंडो केशव कर्वे, और अन्य प्रमुख सामाजिक चिंतक, जिन्होंने न केवल देवदासी प्रथा की प्रथा पर सवाल उठाया और इसके उन्मूलन के लिए दृढ़ता से कहा। उन्होंने सभी समारोहों और प्रक्रियाओं को समाप्त कर दिया, जिसके द्वारा लड़कियों ने खुद को हिंदू तीर्थस्थलों की देवदासियों के रूप में समर्पित किया। उन्होंने देवदासी व्यवस्था के खिलाफ जनमत बनाने के लिए अपने लेखन और सार्वजनिक भाषणों के माध्यम से जनता का ध्यान आकर्षित किया। इस चिंता में, 1892 में भारत के वाइसराय और गवर्नर जनरल और मद्रास के गवर्नर से भी अपील की गई थी। धीरे–धीरे लोकप्रिय

पत्रिकाओं और अखबारों जैसे कि द इंडियन सोशल रिफॉर्मर और लाहौर पवित्रता सेवक सुधारकों ने इस प्रथा के उन्मूलन के लिए सार्वजनिक पक्ष हासिल करने की कोशिश की। इस आंदोलन ने लोगों को नच पार्टियों में शामिल होने से मना करने के साथ–साथ देवदासियों को उत्सव में आमंत्रित करने से मना करने के लिए प्रेरित किया। घरों। 1899 के आसपास, छंनजबी और प्यूरिटन आंदोलन ने समर्पितताओं को रोकने के लिए अपना ध्यान आकर्षित किया। नौच विरोधी आंदोलन ने समर्पण आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया। इस विरोधी दावदासी आंदोलन को थियोसोफिकल सोसायटी से मजबूत समर्थन मिला, जो पश्चिमी वैज्ञानिक स्वभाव पर आधारित था। प्रसिद्ध नृत्यांगना रुक्मिणी देवी अरुंडला, जो थियोसोफिस्ट थीं, ने देवदासी के नृत्य रूप को बदल दिया और इसे भरतनाट्यम के रूप में आधुनिक शैली का नाम दिया। उसने देवदासी की संस्था के आदर्शवादी दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। उनके विचार के अनुसार, यह प्राचीन मंदिर नर्तकी के रूप में शुद्ध, पवित्र और पवित्र महिलाओं के आदर्श थे, क्योंकि वे मूल रूप से थीं। उन्होंने जोर देकर कहा कि देवदासी का नृत्य एक व्यक्ति के आध्यात्मिक विमान को बढ़ाने के लिए ष्नाट्य योगष का एक रूप था। परिणामस्वरूप, कई ब्राह्मण लड़कियों ने देवदासियों से नृत्य सीखना शुरू कर दिया।

इसके साथ ही कानून में देवदासी के उन्मूलन की मांग जारी रही और देवदासी प्रणाली को रेखांकित करने की पहली कानूनी पहल 1934 में बॉम्बे देवदासी संरक्षण अधिनियम के रूप में आई। यह अधिनियम बंबई प्रांत से संबंधित था क्योंकि यह ब्रिटिश राज में अस्तित्व में था। बॉम्बे देवदासी संरक्षण अधिनियम ने महिलाओं के प्रति समर्पण को गैरकानूनी बना दिया, चाहे सहमति हो या न हो। इस अधिनियम के अनुसार, एक देवदासी द्वारा विवाह को वैध और वैध माना जाता था, और इस तरह के विवाह से बच्चों को वैध माना जाता था। अधिनियम में दंडात्मक कार्रवाई के लिए आधार भी निर्धारित किए गए थे जो कि समर्पित होने वाली महिला को छोड़कर किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को समर्पित करने में शामिल हो सकते हैं। इस तरह के कृत्यों के दोषी पाए जाने वालों को एक साल की कैद, जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है। 1934 अधिनियम ने भी नियम प्रदान किए, जिनका उद्देश्य देवदासियों के हितों की रक्षा करना था। जब भी देवदासी को शामिल करने के लिए भूमि के स्वामित्व पर विवाद होता था, तो स्थानीय कलेक्टर से हस्तक्षेप करने की अपेक्षा की जाती थी। 1947 में, स्वतंत्रता का वर्ष, मद्रास देवदासी (समर्पण निवारण) अधिनियम ने दक्षिणी मद्रास प्रेसीडेंसी में समर्पण को रद्द कर दिया। देवदासी प्रणाली को 1988 में पूरे भारत में बंद कर दिया गया था, लेकिन दुर्भाग्य से आज भी भारत के कई हिस्सों में देवदासियों के इस प्रथा को गैरकानूनी रूप से प्रचलित किया जाता है।

महिला शिक्षा के लिए प्रयास

अंग्रेज आर्थिक उद्देश्य वाले व्यापारियों के रूप में भारत आए। वे शायद ही सामाजिक पारंपरिक मानदंडों में हस्तक्षेप करते थे। लेकिन अपने प्रशासनिक सेटअप के दौरान, उन्होंने दो बड़े बदलाव लाए, पहले उन्होंने क्रिस्टन मिशनरियों को अपने यहाँ काम करने की अनुमति दी और दूसरा, उन्होंने भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा सेटअप पेश किया, जिसके परिणामस्वरूप भारत में सामाजिक–सांस्कृतिक सुधार के आंदोलन हुए और इन सुधारों का केंद्रीय मुद्दा महिलाओं का था। क्रिश्चियन मिशनरियों के साथ शुरू करने के लिए वे महिलाओं की शिक्षा के लिए बुनियादी सुविधाओं के लिए आवाज उठाया। जब तक ब्रिटिश उपमहाद्वीप में प्रवेश करते थे, तब तक महिला शिक्षा का अनुपात बहुत कम था। केवल उच्च जातियों की महिलाओं को ही शिक्षा दी जाती थी, जिसमें केवल धार्मिक पुस्तकें और घर के संचालन के लिए कुछ बुनियादी शिक्षा शामिल थी। महिला शिक्षा अनौपचारिक थी। ज्यादातर वे व्यावहारिक मामलों सिखाया जाता था। केवल रक्षित परिवारों की महिलाओं को शास्त्रीय या शाब्दिक साहित्य सीखना चाहिए था। इस समय के बहुत कम उदाहरण बताते हैं कि महिलाओं को खाते रखने में कुछ शिक्षा भी दी गई थी। मोटे तौर पर, बहुसंख्यक मुक्त महिलाएं केवल घरेलू मामलों की शिक्षा जानती थीं। पहले, पश्चिमी शिक्षा प्रणाली के प्रचार के तहत, पहला हिंदू कॉलेज कलकत्ता में 1816 में खोला गया था। अमीर भारतीयों के संरक्षण के आधार पर तीन दशकों में पूरे ब्रिटिश भारत में कई स्कूल खोले गए। लेकिन उनमें से अधिकांश ने केवल लड़के की शिक्षा को बढ़ावा दिया, क्योंकि वे लड़की की शिक्षा में रुचि नहीं रखते थे। इसका मुख्य कारण अंग्रेजों का स्वार्थ था। वे अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने थे केवल कुछ बिचौलियों जो न केवल उनकी भाषा को समझते हैं लेकिन देशी भाषाओं का अनुवाद करने में उन्हें मददकर सकता है पाने के लिए। यह वह समय था जब क्रिस्टन मिशनरियों ने भारत में प्रवेश किया और ष्व्हाइट मैनज बर्डेनष की विचारधारा के तहत बहुत सारे सामाजिक कार्य किए। उन्होंने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार पर बहुत दबाव डाला। लाभार्थी हिस्सा वे शिक्षक थे जिन्होंने भारतीय परिवारों को पढ़ाया था। धीरे–धीरे, शिक्षित पहली पीढ़ी आगे आई और इस दिशा में अपने प्रयासों को सख्ती से शुरू किया। पहली महिला राधा कांता देब, जो कलकत्ता स्कूल सोसाइटी की सचिव थीं, लड़कियों की शिक्षा की संरक्षक बनीं। उन्होंने 1819 में स्थापित कलकत्ता फीमेल जुवेनाइल सोसाइटी के गठन में सहायता की। आने वाले दस वर्षों में क्रिस्टन मिशनरी सोसाइटी की मदद से उन्होंने हिंदू लड़कियों के लिए तीस स्कूल खोले। इन स्कूलों को कुलीन वर्ग से संरक्षण मिला। लेकिन वे छात्राओं को आकर्षित करने में असफल रहे। इसका मुख्य कारण उचित नीति का अभाव था। क्रिस्टन मिशनरियों ने इस चिंता में उल्लेखनीय काम किया। उन्होंने 1840 तक मुफ्त किताबें और कपड़े आदि प्रदान किए। स्कॉटिश चर्च सोसायटी ने दावा किया कि 200 लड़कियों की ताकत वाले छह स्कूल हैं। लेकिन अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली भारतीयों की प्रबल पक्षधर नहीं थी। वे चाहते थे कि शिक्षा पूरी तरह से सेक्स लाइनों पर विभाजित हो, इसका मतलब है कि लड़कियों और लड़कों को एक स्कूल में नहीं पढ़ना चाहिए। लड़कियों के पास केवल महिला शिक्षक के साथ अलग शैक्षणिक संस्थान होने चाहिए और उन्हें सीमित विषयों में शिक्षा मिलेगी, जो कि कर्तव्यों में लाभकारी होगी। यहां तक कि देश के कई हिस्सों में परदा सीसेम लागू किया गया था। जिसमें शिक्षक और छात्रों के बीच एक परदे या पर्दे को लटका दिया गया था।

भारत का अठारहवीं शताब्दी का इतिहास सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों से चिह्नित है। उन्होंने महिलाओं के

उत्थान के लिए बहुत सारे काम किए। कई सुधारक सुधारकों ने अपने घरों से इन सुधारों को शुरू किया। उनके लिए यह स्पष्ट था कि सभी महिलाओं के मूल कारणों में विधवापन की समस्या, सती प्रथा, बाल विवाह और देवदासी प्रथा जैसी बुनियादी समस्याएँ स्त्री शिक्षा का अभाव है। उन्होंने अपनी महिलाओं को पढ़ाना शुरू किया और इस तरह से महिला नेताओं का पहला शिक्षित समूह सामने आया जिसने भविष्य में महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। कई सामाजिक सुधार आंदोलनों जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, आर्य समाज, थियोसोफिकल सोसायटी और देव समाज आदि ने महिला शिक्षा के पक्ष में अपनी आवाज दी। यह अनुमान है कि 1854 तक लगभग 626 लड़कियों के स्कूल थे, जिनमें बंगाल में 288, मद्रास में 256, बॉम्बे में 65, एनडब्ल्यूएफपी में 17 और अवध में कुल 21, 755 छात्र थे। यह बहुत कम संख्या थी लेकिन रूढ़िवादी हिंदू समाज में परिवर्तन का संकेत था। सामाजिक सुधार लाने के लिए कई भारतीयों ने महिला शिक्षा का स्वागत किया। ब्रिटिश लोगों ने वित्तीय और प्रशासनिक जरूरतों के तहत शिक्षा को बढ़ावा दिया। समाज सुधारकों ने महिला शिक्षा को सामाजिक सुधार के रूप में देखा। वे केवल उन्हें शिक्षित करना चाहते थे कि उन्हें पढ़ना और लिखना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो उनके आंदोलनों के लिए उनके साथ खड़े हो सकते हैं। उनमें पहला काम ब्रह्म समाज ने किया था। उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल और कॉलेज खोले। 1883 में पहली कादम्बिनी बसु और चंद्रमुखी बसु ने अपनी बीए की डिग्री यहाँ से प्राप्त की और ब्रिटिश भारत में पहली स्नातक बनीं।

1882 के भारतीय शिक्षा आयोग ने लड़कियों की शिक्षा के सवाल पर टिप्पणी की कि ष्महिला शिक्षा अभी भी अत्यंत पिछड़ी स्थिति में है और इसे हर वैध तरीके से लागू करने की आवश्यकता है।ष लेकिन बहुत जल्द ही भावुक और भौतिक कारणों के कारण निष्क्रिय उदासीनता की भावना को सक्रिय सहानुभूति में बदल दिया गया। शिक्षा विभागों ने भी कुछ सक्रिय कदम उठाए और लड़कियों के लिए शिक्षा के अलग–अलग स्कूलों के प्रसार के लिए नई योजनाएं तैयार कीं। लड़कियों को स्कूलों में ले जाने की व्यवस्था की गई। निरीक्षकों को नियुक्त किया गया था, निजी लड़कियों के स्कूलों में अनुकूल अनुदान दिया गया था, और महिलाओं को शिक्षण पेशे के लिए आकर्षित करने के लिए कदम उठाए गए थे।

उपरोक्त कदमों ने लड़कियों की शिक्षा को बहुत प्रोत्साहन दिया। 1884 में, श्रीमती एनी बेसेंट ने बनारस (वाराणसी) में सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल की स्थापना की, जो हिंदू धर्म के आधुनिक स्कूल में लड़कों से लड़कियों को अलग से पश्चिमी शिक्षा देने के उद्देश्य से था। 1916 में देश में पहली बार सेक्स करने के लिए मेडिकल कॉलेज लेडी हार्डिंग कॉलेज, दिल्ली की स्थापना की गई। महिला (एसएनडीटी) विश्वविद्यालय भी उसी वर्ष स्थापित किया गया था। दक्षिण भारत में, इस चिंता में मुख्य कार्य थियोसोफिकल सोसायटी द्वारा किया गया था। एनी बेसेंट द्वारा नेतृत्व में, उन्होंने ष्ओल्डन एज पर वापसीष के नारे के तहत अपना काम शुरू किया। उन्होंने कई स्कूल खोले और अपने मिशन को घर–घर जाकर "घर की रोशनी" में बदलने के लिए प्रेरित किया। दिसंबर 1884 में मद्रास में आयोजित दक्षिण भारतीय सम्मेलन ने महिला शिक्षा के पक्ष में प्रस्ताव पारित किए। 1895 में कलकत्ता में आयोजित दसवें सम्मेलन में पारित अपने प्रस्तावों के माध्यम से, भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन (प्छैब) ने जोर दिया

- ंमहिला शिक्षकों को महिला स्कूलों में नियोजित किया जाना चाहिए,
- महिलाओं के लिए प्रशिक्षण स्कूल पर्याप्त संख्या में योग्य महिला शिक्षकों को सुरक्षित करने के लिए स्थापित किए जाने चाहिए
- बड़ी महिलाओं के लिए घर की कक्षाएं संचालित की जानी चाहिए सी। महिला स्कूलों के लिए पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित होनी चाहिए और घ।
- सुई काम, स्वच्छता, पाक कला, घरेलू अर्थव्यवस्था में निर्देश महिलाओं को प्रदान किया जाना चाहिए।

बीसवीं सदी के अंत तक स्कूलों में महिलाओं का नामांकन कई गुना बढ़ गया। इसने हमारे देश में महान परिवर्तन खरीदा लेकिन शैक्षिक क्रांति को नजरअंदाज कर दिया गया। दूसरी ओर, इसका कड़ा विरोध हुआ कि भारतीय महिलाओं के लिए पश्चिमी पैटर्न आधारित शिक्षा को स्वीकार करते हुए, उन्हें पश्चिमी महिलाओं के बराबर बनाने या उन्हें पेशेवर रूप से प्रशिक्षित करने के लिए नहीं बनाया गया था। उन्हें माताओं, बहनों, बेटियों और पत्नियों के रूप में बेहतर प्रदर्शन के लिए शिक्षित किया जाना चाहिए। परिणामस्वरूप, बॉम्बे की सरकार, शैक्षिक विभाग संकल्प सं। 1143, बॉम्बे कैसल, 30 अप्रैल 1917, में कहा गया है कि निचले प्राथमिक मानकों में लड़कियों को सिखाया जाना चाहिए कि कैसे पढ़ना, लिखना, साथ में सुईटवर्क, धार्मिक सिद्धांत और शारीरिक व्यायाम। उच्च प्राथमिक मानकों में, कुकरी के कुछ ज्ञान को भी शामिल किया जाना चाहिए। 1919 में पूना सेवा सदन द्वारा भारत सरकार के संकल्प की सराहना की गई, जिसने अपनी छात्राओं को नर्सों, दाइयों, सहायक शल्य चिकित्सकों, कला और शिल्प कार्यशाला में प्रशिक्षित शिक्षा दी। इस अवधि के दौरान, यह सर्वेक्षण किया गया था कि साठ प्रतिशत से अधिक महिलाएं विशेष महिला संस्थानों में जा रही हैं। परिणामस्वरूप, कई विशेष रूप से महिला संस्थान जैसे प्राच्य महाविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, कृषि महाविद्यालय और कला विद्यालय आदि खोले गए। ैप के अंत तक, भारत के सभी राज्यों में लड़कियों के स्कूल थे और लड़कियों के छात्रों के नामांकन में भी वृद्धि हुई थी। अब राय बेहतर पत्नियों और बेहतर माताओं को बनाने वाली शिक्षा की ओर बढ़ रही थी। 1917 में 12 कला कॉलेज, चार पेशेवर कॉलेज और लड़कियों के लिए 166 माध्यमिक स्कूल थे। हालाँकि अधिकांश लड़कियों ने लंबे समय तक स्कूलों में अपनी पढ़ाई जारी नहीं रखी। 1900–1947 के बीच भारत की महिलाओं को उन्नीसवीं शताब्दी के सामाजिक सुधारों और शैक्षिक प्रयासों के लाभार्थियों के रूप में शिक्षित किया गया, एक नया बदलाव शुरू हुआ।

महिला संघों द्वारा किया गया कार्य

भारत में महिला संघों का इतिहास उन्नीसवीं सदी की महिलाओं और बीसवीं सदी की महिलाओं के बीच बहुत बड़ा अंतर है। शुरुआत में, जैसा कि हम जानते हैं, सुधारों के लिए कदम भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए थे और यह काम मुख्य रूप से पुरुष सुधारकों द्वारा ब्रिटिश भारत में परिवर्तन के प्रतिनिधि होने के रूप में किया

गया था। इसलिए, शुरुआती महिलाओं के आंदोलन ने श्परिवर्तनश के लिए उठाए गए मुद्दों को बाधित किया। मुद्दे काफी हद तक वे थे जो उच्च जातियों और मध्यम वर्गों जैसे विधवा पुनर्विवाह, दहेज, बहुविवाह और संपत्ति के अधिकारों को मिटाते थे। सभी महिलाओं के सवाल देश के बड़े हिस्से में थे। इस चरण के मुद्दों के दौरान सार्वजनिक जीवन में बदलाव का मतलब स्वीकार किया गया, जाति और लिंग दोनों में समान नागरिकों की बहुत धारणा को स्वीकार नहीं किया गया। मुख्य रूप से, निजी क्षेत्र में समानता को स्वीकार नहीं किया गया था, उदाहरण के लिए, विरासत के अधिकार, घरेलू हिंसा से संबंधित मुद्दे, आदि। शुरुआत में, महिलाओं के अधिकारों के लिए आंदोलनों में भाग लेने वाली अधिकांश महिलाएं, ज्यादातर वे थीं जो उन परिवारों से थीं जहाँ पुरुष कुछ सामाजिक सुधार आंदोलनों में लगे हुए थे। जिन्होंने न केवल महिलाओं के लिए आवाज उठाई बल्कि अपनी महिलाओं को इसके लिए सक्षम बनाया। उन्होंने अपनी महिलाओं को शिक्षा दी और उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए मार्गदर्शन किया। ये महिलाएं अपने घरों से बाहर आईं और सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संघों की विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया। शिक्षित कुलीनों के लिए, दो मुद्दे केंद्रीय महत्व के थे। ये उनकी शक्ति और धन बढ़ने के साथ उनकी कार्रवाई को प्रेरित करने वाले मुख्य कारक थे।

पहला था, किस तरह से उत्तराधिकार को औचित्य दिया जाए और दूसरा, नई सांस्कृतिक पहचान कैसे बनाई जाए। इसके लिए उन्होंने एक विचारधारा को विकसित या अपनाया और अपने मुद्दों को हल करने की रणनीति बनाई, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न संघों का गठन हुआ। इसलिए, यह तीन स्तरों पर सामने आया, सबसे प्रमुख अभिजात वर्ग का प्रतिनिधित्व था, दूसरे स्तर पर ऊर्ध्वाधर जनसमूह था और जमीन पर सामूहिक जुटान थे। महिला आंदोलन बहुसंख्यक अभिजात्य वर्ग में केंद्रीकृत थे। इसके लिए तीन तीन मुख्य कारक जिम्मेदार थे। पहला, शिक्षा जो जागरूकता का मुख्य कारण कुलीन वर्ग तक सीमित थी, दूसरा शुरुआत में महिलाओं के लिए मुख्य कार्य क्रिसमस मिशनरियों द्वारा किया गया था और भारतीयों ने अपनी महिलाओं को धर्मांतरण के डर से उनके साथ बातचीत करने की अनुमति नहीं दी थी और तीसरा यह था कि ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे पर उनका उत्साही रुख नहीं दिखाया, क्योंकि उन्हें हस्तक्षेप के कारण विद्रोह की आशंका थी। ऐसी परिस्थितियों में सबसे पहले व्यक्तिगत भारतीय पुरुषों जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर और बेहरामजी मालाबारी आदि द्वारा प्रयास किए गए, जो कि ब्राह्मो समाज और प्रतिष्ठा समाज जैसे सुधार संगठनों में सक्रिय महिलाओं द्वारा शुरू किए गए प्रयासों के अगले चरण थे। इन शुरुआती संघों को उच्च स्तर के सामाजिक विरोध का सामना करना पड़ा और प्रतिक्रिया में कुछ एसोसिएशन के नेताओं ने महिलाओं के साथ अपने काम को पुनरुत्थानवादी शब्दों में चित्रित करना शुरू किया। लेकिन उन्नीसवीं और बीसवीं सदी के उत्तरार्ध में महिलाओं को दी गई शिक्षा के परिणामस्वरूप महिलाओं को अपने घरों या समुदायों से बाहर शिविर लगाना पड़ा और जिन्होंने अपने मुद्दों को बताना शुरू किया। वे उनके लिए गठित नए क्लबों और संघों में शामिल हो गए। अब, महान काम मौखिक भाषा में किया गया था। इसे पढ़कर वे अपने मुद्दों के साथ–साथ उन सामान्य समस्याओं और कष्टों को आसानी से दूर कर सकते थे, जिनसे वे गुजर रहे थे। इसने इस आंदोलन के आने वाले नेताओं के लिए प्रशिक्षण का आधार भी प्रदान किया। महिलाओं के लिए पहला महिला संगठन बंगाल में ब्रह्म समाज के गतिशील नेता केशव चंद्र सेन द्वारा बनाया गया था। इसी तरह का संगठन प्रथना समाज द्वारा बंबई में खोला गया था। 1882 में जस्टिस रानाडे ने आर्य महिला समाज की स्थापना करने में पंडिता रमाबाई सरस्वती की मदद की। इनमें 1870 के दशक में केशब चंदर सेन (ब्रह्म समाज) द्वारा गठित बंगाल में भारत आश्रम (भारतीय हरमिटेज) शामिल थाय 1880 के दशक में पंडिता रमाबाई और जस्टिस रानाडे द्वारा गठित बंबई में आर्य महिला समाज (आर्य महिला संघ)य 1905 में राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन के भाग के रूप में गठित भारत महिला परिषद (महिला सम्मेलन);

यहां तक कि स्थानीय मुस्लिम महिलाओं के संघों की स्थापना 20 वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत के कई हिस्सों में उच्च वर्ग की महिलाओं द्वारा की गई थी। उदाहरण के लिए, पंजाब में अंजुमन–ए–खवातीन–ए–इस्लाम (मुस्लिम महिला संघ), मियां परिवार के अमीरुन–निसा द्वारा गठित। शफी परिवार की कुछ महिला सदस्यों ने लाहौर में एक संघ शुरू किया। 1916 में भोपाल की बेगम ने अखिल भारतीय मुस्लिम महिला सम्मेलन का गठन किया, जिसमें सामाजिक सुधारों और शिक्षा पर शोधपत्रों को पढ़ा गया और यहाँ तक कि प्रस्ताव भी पारित किए गए। 1917 में, अब्रू बेगम जो अब्दुल कलाम आजाद की बहन थीं, ने बहुविवाह के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया, जिसने विरोध को भड़काया।

राष्ट्रीय आंदोलनों के दौरान इन संघों के लिए अगला महत्वपूर्ण पड़ाव था। पहला, स्वदेशी आंदोलन के दौरान, जिसने बड़े पैमाने पर काम किया और राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की भागीदारी को आसान बनाया। कई त्याग महिला नेता सरलादेवी चौधुरानी की तरह मुख्य राष्ट्रीय फ्रेम में आईं, जिन्हें ष्नई महिलाष के रूप में जाना जाता है, दोनों नारीवादी और राष्ट्रवादी के रूप में। उन्होंने सामाजिक सुधार और राष्ट्रवादी आंदोलनों दोनों में सक्रिय रूप से भाग लिया। वह पहली महिलाओं में से एक थीं, जिन्होंने महिलाओं की आवश्यकता को देखा और एक एसोसिएशन शुरू की। उन्होंने तर्क दिया कि महिलाओं के मुद्दों को राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन के एक संयोजन के रूप में पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया जा सकता है जो 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्थापित किया गया था। इसलिए, उन्होंने भारत स्ट्री महामंडल (महान) की स्थापना की

1910 में इलाहाबाद में भारतीय महिलाओं का समूह। सरला देवी के प्रयासों से भारत के विभिन्न हिस्सों में कई महिलाओं के क्लब, समूह और संघों का गठन हुआ।

जल्द ही इसके परिणामस्वरूप 20 वीं सदी के शुरुआती दशकों में महिला–केवल संघों (जिन्हें ज्यादातर महिला समितियां कहा जाता है) का आयोजन किया गया। इन स्थानीय संघों ने महिलाओं के राष्ट्रीय संघों के लिए आधारशिला रखी। राष्ट्रवादी आंदोलन के शुरुआती दौर में, महिला भारतीय संघ को (1917) हड़काया गया, उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर।

भारतीय महिला परिषद (1925) और अखिल भारतीय महिला सम्मेलन (1927) इन संघों का सिद्धांत यह था कि वे सभी जातियों, संस्कृतियों और धर्मों की महिलाओं को शामिल

RRIJM 2015, All Rights Reserved

और उनका प्रतिनिधित्व करते थे। इसने दक्षिण भारत के विभिन्न हिस्सों में शाखाएँ भी खोलीं और मद्रास थियोसोफिकल सोसायटी से जुड़ीं जो महिलाओं के लिए काम कर रही थीं और सबसे लोकप्रिय संगठन था। अगला कदम 1917 में महिला मताधिकार का तर्क था। परिणामस्वरूप, 1929 तक, सभी प्रांतीय विधानसभाओं ने महिलाओं को मतदान का अधिकार दे दिया था। यह वही वर्ष है जब ऑल इनिया महिला परिषद का गठन किया गया था। 1937 में विभिन्न प्रांतों में लगभग 60 महिलाएँ प्रांतीय विधानसभाओं की सदस्य बनीं। इस प्रकार, महिला संगठनों ने राजनीतिक अधिकारों और पुरुषों के साथ समानता के लिए लड़ाई लड़ी। यद्यपि उनका प्रयास आंशिक सफलता पाने में कामयाब रहा, लेकिन उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए अपना आंदोलन जारी रखा। इसने भारत के लोगों में जागरूकता पैदा की।

निष्कर्ष

उपरोक्त चर्चाओं से यह स्पष्ट होता है कि महिलाओं की दयनीय स्थिति ने सुधारकों को लंबे समय तक महिलाओं के उत्थान के लिए प्रचार और प्रसार करने के लिए आमंत्रित किया। हालाँकि, 19 वीं शताब्दी में महिलाओं के सामाजिक कष्टों को कम करने के लिए समाज सुधारकों द्वारा बहुत मजबूत और व्यावहारिक कदम उठाए गए थे। महिलाओं को यह एहसास था कि उनके सामाजिक कष्टों को उनकी आर्थिक निर्भरता और संयुक्त परिवार प्रणाली के साथ जोड़ा गया था, लेकिन पहले वे अपनी सामाजिक अक्षमताओं को दूर करना चाहते थे और अपने स्वास्थ्य और सामाजिक स्थिति को बढ़ाते थे। इस प्रकार, प्रयासों ने आर्थिक रूप से और फिर सामाजिक रूप से महिलाओं के उत्थान की आवश्यकता पर जागरूकता पैदा की। मिशनरियों के निरंतर काम के परिणामस्वरूप पंजाब के समाज के निचले तबके में भी शिक्षित समुदाय का निर्माण हुआ। महिलाएँ शिक्षक बन गईं, नर्सेय सरकारी अधिकारी और यहां तक कि मिशनरी सहायक। इस प्रकार, 19 वीं शताब्दी के अंत में महिला शिक्षा के लिए संपूर्ण जनमत को गति में स्थापित किया गया। हालांकि, ब्रिटिश सरकार की मदद से 19 वीं सदी का सामाजिक सुधार आंदोलन 20 वीं सदी में प्रभावित महिलाओं के पुनर्वास के नए विचार के साथ जारी रहा।

संदर्भ

1. सतीरू विनियमनXVII, 1829 ई।, लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक के पत्राचार में, एड। ६भ. फिलिप्स, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। 1977 1रू 1828–1831।
2. सुमित सरकार, तनिका सरकार। (संपादक)। आधुनिक भारत में महिला और सामाजिक सुधाररू एक पाठक। इंडियाना यूनिवर्सिटी प्रेस, 2011।
3. चक्रवर्ती, उमा। नारीवादी लेंस के माध्यम से जाति का प्रतिपादन। लोकप्रिय प्रकाशन, 2011।
4. फोर्ब्स, जेराल्डिन। आधुनिक भारत में महिलाएं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 2011।
5. साथियों, औपनिवेशिक शासन के तहत डगलस एम। इंडियारू 1700–1885। पियर्सन एजुकेशन, 2011।
6. गेराल्डिन फोर्ब्स, द कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वूमन इन मॉडर्न इंडिया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 2009।
7. जानकी नायर। औपनिवेशिक भारत में महिला और कानून, भारत विश्वविद्यालय, राज प्रेस, 1996 के राष्ट्र कानून स्कूल के सहयोग से प्रकाशित।
8. अल्टेकर के रूप में। हिंदू सभ्यता में महिलाओं की स्थिति, बनारसरू मोतीलाल बनारसी दास, 1956।
9. देसाई नीरा। भारत में महिलाएं, बॉम्बेरू वोरा पब्लिशर्स, 1957।
10. साहू बीबी। देवदासी प्रणाली का पुनरुद्धार, इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क। 1997, 58 (3)।
11. एवरेट जेएम। वूमेन एंड सोशल चेंज इन इंडिया, हेरिटेज पब्लिशर्स, 1985।

RRIJM 2015, All Rights Reserved